शहरी समाचार

नई सोच नई पहल

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

मई, 2022 | वर्ष 02 | अंक 05 | नगरीय बुलेटिन | पृष्ठ :12 | मूल्यः निःशुल्क

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

DAY-NULM
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission

आत्मनिर्भर भारत

16,804	30,025	86,772	57,647
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन	पीएम स्वनिधि ऋण वितरित	PMAY(U) आवासों का निर्माण पूर्ण	मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) जॉब कार्ड वितरित

Innovative Construction Technologies
क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए पहल

पीएम आवास के कार्यों में गति लाने के लिए मुहिम हुई तेज

रामगढ़ नगर परिषद की नयी पहल, लाभुक रोजगार अभियान

अनुक्रमणिका

Innovative Construction Technologies क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए पहल

PMAY (U) घटक-4 को ससमय पूरा करना पहली प्राथमिकता

सकारात्मक आवासीय परिवेश की रचना में PMAY (U) का अहम योगदान

पीएम आवास के कार्यों में गति लाने के लिए मुहिम हुई तेज

पीएम स्वनिधि का मिला सहारा, मुश्किलों से हुआ किनारा

आर्या स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ पेश कर रहीं हैं सफलता की नजीर

चेहरे पर खिल उठी मुस्कान पीएम आवास योजना से मिला पक्का मकान

नेतृत्व, उद्यमशीलता एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने का हो रहा प्रयास

रामगढ़ नगर परिषद की नयी पहल, लाभुक रोजगार अभियान

डे-एनयूएलएम योजना से जुड़ कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं शहरी गरीब

युवाओं को हुनरमंद एवं रोजगारपरक ट्रेनिंग देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश

औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की गाथा

संदेश

नमस्कार! सर्वप्रथम आप सभी पाठकों को आपसी भाईचारे एवं स्नेह का पवित्र पर्व ईद-उल-फितर की बधाई एवं शुभकामनाएं।

मुझे प्रसन्नता के साथ-साथ गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हर माह की भांति इस माह भी नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा विकास के कार्यों में भूमिका, कई प्रकार के अध्ययन साकार करने एवं प्रोत्साहन क्षमता विकास के उद्देश्य से 'शहरी समाचार' के द्वितीय वर्ष का पांचवां अंक "मई 2022" प्रकाशित किया जा रहा है।

निदेशालय के तत्वावधान में राज्य भर के नगर निकायों में संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं विभिन्न कार्यों से संबंधित कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखों का संकलन कर हम इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। जिससे की उद्देश्य पूर्ण विषयों से जुड़े पहलुओं पर पाठकों को सारगर्भित सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप शहरी आवास विहीनों को सुरक्षित व बुनियादी सुविधायुक्त पक्का मकान, उद्यमशीलता एवं आत्मनिर्भरता से महिला सशक्तिकरण की स्थिति में निरंतर सुधार एवं युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है, जिसके चलते राज्य को विश्वपटल पर नई पहचान मिल रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगातार उल्लेखनीय प्रगति से मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए वित्तीय वर्ष में भी निदेशालय अपने दायित्वों के निर्वहन में ऊंचाइयों को छूते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

मुझे मालूम है कि किसी भी पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। लेखों के संकलन और प्रकाशन में सभी सतर्कताओं को अपनाया गया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो, तो प्रबुद्ध पाठक उन त्रुटियों के इत्तर विषय-वस्तु को समझेंगें ऐसा मेरा विश्वास है।

जिस प्रकार निदेशालय नित नई ऊंचाईयों को छू रही है उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे सभी आनुषांगिक इकाइयां एवं सभी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं प्रकाशित लेखों के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में इसी सकारात्मक संकल्पना और अवधारणा के साथ मैं अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने की अपील करता हूँ और बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही आशा करता हूँ कि "शहरी समाचार" का यह नवीन अंक हम सभी के लिए प्रेरणादायी व ज्ञानवर्द्धक साबित होगा।

मैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री राजेश कुमार पाठक (भा.प्र.से.)
निदेशक,
नगरीय प्रशासन निदेशालय।

Innovative Construction Technologies क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए पहल

झारखंड से हुआ रचना कार्यक्रम का आगाज

डीएमए, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशक श्री राजेश कुमार पाठक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए।

- किफायती आवास में MoHUA की रचनात्मक पहल
- आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभर में 75 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का होगा आयोजन
- RACHNA-Resilient, Affordable and Comfortable Housing Through National Action

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देश के अलग-अलग प्रदेशों में चल रहे किफायती आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी का उपयोग, थर्मल कम्फर्ट को शामिल करने एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार, GIZ, BMTPC एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में रचना नामक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसकी शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से हुई। जिसके तहत दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को Innovative Construction Technologies & Thermal Comfort for Affordable Housing विषय पर रांची के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम, जुपमी बिल्डिंग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन निर्माण क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों हितग्राहियों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य Innovative Construction Technologies एवं किफ़ायती आवास निर्माण में थर्मल कंफर्ट की भूमिका, क्लाइमेट अनुकूल स्मार्ट बिल्डिंग के निर्माण संबन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा करना था।

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नयी तकनीकों के इस्तेमाल के लिए एक दिवसीय कार्यशाला "रचना" का आयोजन

भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरूआत दीप प्रज्वलित कर करने की परंपरा रही है। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। इसी उद्देश्य अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमए निदेशालय के निदेशक श्री राजेश कुमार पाठक (भा. प्र. से.), नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्य टाउन प्लानर श्री गजानंद राम, श्री सी.एन. झा, डिप्टी चीफ, (BMTPC), हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख श्री अजित कुमार एवं प्रोग्राम हेड केविकास रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डीएमए के सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी एवं श्री योगेन्द्र प्रसाद, PMAY(U) कोषांग के सभी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ सहित डीएमए के समस्त अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रतिभागी के रूप में टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र एवं प्रोफेसर, जूडको एवं रांची नगर निगम के अभियंता, स्मार्ट सिटी के अभियंता एवं आवास निर्माण के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी काफी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण के दौरान श्री शैलेश प्रियदर्शी, सहायक निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय (डीएमए) ने भवन और निर्माण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया।

प्रशिक्षण में थर्मल कम्फर्ट से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं जैसे भौतिक प्रभाव, कम लागत वाले समाधान शामिल थे, जो भारत में जलवायु-स्मार्ट बिल्डिंग बनाने के लिए उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य किफ़ायती आवास क्षेत्र में हितधारकों को थर्मल कम्फर्ट की आवश्यकता से अवगत कराना एवं आगामी परियोजनाओं में कम लागत वाली रणनीतियों पर चर्चा करना भी शामिल था।

किफ़ायती आवास परियोजना में इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड थर्मल कम्फर्ट का सम्मलित होना एक बड़ी प्राकृतिक क्षमता की पहचान कराएगा। साथ ही थर्मल आराम के मानकों के अनुपालन को प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टलिस्टेड किफ़ायती आवास परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के कार्यान्वयन के दायरे को आगे बढ़ाते हुए PMAY(U) मिशन के तहत थर्मल रूप से आरामदायक आवास के निर्माण को बढ़ाने की दिशा में एक मील का भी पत्थर है।

कार्यक्रम में BMTPC के डिप्टी चीफ श्री सी. एन. झा ने रांची में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट की तकनीकी विशेषताओं, प्रीकास्ट कंकरीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D वॉल्यूमेट्री के बारे विस्तारपूर्वक बताया। साथ ही उन्होंने भविष्य में बढ़ती शहरी जनसंख्या को देखते हुए इस तरह की परियोजनाओं के व्यापक कार्यान्वन पर जोर दिया। श्री एस. विकास रंजन, प्रोग्राम हेड, जीआईजेड ने देश में क्लाइमेट स्मार्ट बिल्डिंग्स (सीएसबी) और इसके अनुप्रयोगों के महत्व पर प्रकाश डाला और यह बताया कि इस नए तकनीक का उपयोग करना लक्ष्य प्राप्त करने का एक सही कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन घरों का निर्माण और संचालन अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से ऊर्जा के जरूरतों पर निर्भरता को कम करेगा।

RACHNA
RESILIENT, AFFORDABLE AND COMFORTABLE HOUSING THROUGH NATION ACTION
GLOBAL HOUSING TECHNOLOGY CHALLENGE INDIA

कार्यक्रम में किफ़ायती आवासों के निर्माण और संचालन में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करना एवं निर्मित आवासों में दैनिक जीवन के आयामों में थर्मल कम्फर्ट को बढ़ावा देने से सम्बंधित विभिन पहलुओं पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मास्टर ट्रेनर श्री सैबाल साहा एवं श्री कुमार विप्लव ने विस्तारपूर्वक प्रस्तुति दी। जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के संकल्पों के साथ पौधा वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

आवास मनुष्य की आधारभूत जरूरतों में से एक है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) गरीबों एवं शहरी आवासविहीनों के जीवन को नया आयाम दे रहा है। साथ ही योजना के सफल कार्यान्वयन से गरीबों एवं शहरी आवासविहीनों के जीवन में व्यापक समाजिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जिसको हम देश भर में आयोजित किये जा रहे लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम के आंकड़ों से भी समझ सकतें हैं। परन्तु इन सभी स्थितियों के बावजुद हमें भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। आज हम जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ती जनसंख्या जैसी व्यापक समस्या का सामना कर रहें हैं। इसलिए हमें आने वाले परिवर्तनों को देखते हुए आवास निर्माण के क्षेत्र में नयी तकनीकों, थर्मल कम्फर्ट दैनिक जीवन ऊर्जा जरूरतों को कम करने वाले उपाय एवं ऊर्जा के नए विकल्पों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को बढ़ावा देने की जरुरत है। ताकि, भविष्य में बेहतर आवासीय संरचना के साथ-साथ आने वाले चुनौतियों का सामना किया जा सके एवं गरीबों को बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध कराई जा सके। प्रीकास्ट कंकरीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम **3D** वॉल्यूमेट्री तकनीक से रांची में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है।

–श्री राजेश कुमार पाठक
(भा. प्र. से.),
निदेशक, डीएमए
(झारखण्ड सरकार)।

PMAY (U) घटक-4 को ससमय पूरा करना पहली प्राथमिकता

नये वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 25443 आवासों का तीव्रगति से निर्माण के लिए नियमित बैठकों का दौर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। नगरीय प्रशासन निदेशालय का इस अतिकल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजना को नए वित्तीय वर्ष में भी सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर पूरे राज्य को लाभान्वित करने का प्रयास अनवरत जारी है। निदेशालय, निकायवार कार्य योजना के लक्ष्य की प्राप्ति, कार्यों की प्रगति, समन्वय के स्रोतों की पहचान एवं समयबद्ध तरीके से योजना अंतर्गत विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रही है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निदेशक श्री राजेश कुमार पाठक (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2022 एवं 27.04.2022 को राज्यस्तरीय ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएमए के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े राज्य स्तरीय पदाधिकारियों सहित राज्य के सभी नगर निकायों के पदाधिकारी गण, नगर प्रबंधक एवं CLTC विशेषज्ञ सम्मिलित हुए।

गिरिडीह को बड़ी सौगात, PMAY(U) के BLC घटक अंतर्गत 3347 आवास स्वीकृत

दिनांक 13.04.2022 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चौथे घटक (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण-BLC) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 46 शहरी नगर निकायों में स्वीकृत कुल 25,443 आवासों के जल्द निर्माण, कार्यों में तीव्रता, लाभुकों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं का त्वरित निष्पादन एवं लाभुकों के बीच जागरूकता के लिए विशेष कैंप समेत अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। ताकि, स्वीकृत आवासों के निर्माण के लक्ष्य को ससमय पूरा किया जा सके। लाभुकों के सहूलियत एवं कार्यों में पारदर्शिता के लिए नगर निकायों को सामूहिक रूप से कैंप लगाकर तीन दिनों में लाभुकों के साथ एकरारनामा कराने का लक्ष्य दिया गया। इस अभियान को 21 से 23 अप्रैल 2022 के दौरान नई डीपीआर के तहत बीएलसी लाभार्थियों का एकरारनामे को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया। योजना अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए नगर निकायों को वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट (WPR) उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य प्रगतिशील है।

इसी कड़ी में दिनांक 27.04.2022 को भी श्री राजेश कुमार पाठक, निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएमए के सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी ने योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्तमान में नए वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत आवासों के लिए जिन नगर निकायों ने लक्ष्य के अनुरूप एकरारनामा कार्य को पूरा नही किया, उन्हें 30 अप्रैल 2022 तक शत-प्रतिशत एकरारनामा कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही योजना के घटक-3 (किफ़ायती आवास परियोजना) अंतर्गत विभिन्न कार्यों जैसे भूमि चिन्हित करना, कार्यकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेज सम्बन्धी कार्यों का निपटारा करना इत्यादी कार्यों को यथा शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया।

दिनांक 13.04.2022 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक में निकायों के कार्यों की समीक्षा करते डीएमए के सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी।

किफ़ायती आवास परियोजना के कार्यान्वयन पर विशेष जोर

PMAY(U) के घटक-3 (किफ़ायती आवास परियोजना-AHP) के तहत राज्य भर में निर्माणाधीन परियोजनाओं को ससमय पूरा करने के उद्देश्य से डीएमए के सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी द्वारा नगर निकायों के साथ परियोजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न विषयों एवं चुनौतिओं पर विस्तारपूर्वक पर चर्चा किया गया। उन्होंने नगर निकायों को सलाह दिया कि परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन के लिए बैंको पर निर्भरता कम किया जाना चाहिए। ताकि, दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में बैंकों के साथ समय व्यर्थ ना हो। जो लाभुक एक किश्त चुकाने के बाद दूसरा किश्त देने में सक्षम हैं, उन्हें जागरूक किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निदेश दिया की परियोजना के लिए जो जमीन चिन्हित किए गए हैं, उनका मुआयना कर जल्द से जल्द वहाँ काम प्रारंभ करवाया जाय तथा नक्शा एवं निर्माण से सम्बन्धीत विभिन्न समस्याओं के लिए अधिकृत परिचालन एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित कर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।

सकारात्मक आवासीय परिवेश की रचना में PMAY (U) का अहम योगदान

मानगो नगर निगम अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) घटक 4 के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन सस्टेशन, बैंगलोर की टीम द्वारा किया गया। टीम के सदस्यों के द्वारा लाभुकों के घर जाकर लाभुकों द्वारा बनाये गए आवासों का मुआयना किया एवं लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से होने वाले लाभ एवं इससे उनके जीवन स्तर में सुधार की समीक्षा की गई। साथ ही आवास निर्माण के समय लाभुकों को और बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया। टीम के द्वारा निरीक्षण के क्रम में लाभुकों से वार्तालाप कर एवं स्वच्छ व सुंदर घर को देखकर संतुष्टि जाहिर की गई। लाभार्थियों के साथ आवास निर्माण एवं नए आवास मिलने के बाद जीवन में आए परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक बातचीत कर उनके जीवन में आये बदलावों को जानने का प्रयास किया गया। साथ ही लाभार्थियों के परिवारों से परिचय प्राप्त कर आजीविका संबंधी बातों की भी जानकारी ली गयी। लाभार्थियों ने टीम के सदस्यों के साथ अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आवास निर्माण से पूर्व कच्चा मकान में रहने के दौरान बच्चों का लालन-पालन करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। जीवन अंधकारमय हो गया था। कच्चे मकान की दीवार गिरने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। साथ ही सगे-संबंधियों व समाज में मान-सम्मान घट गया था। लेकिन, जैसे ही आवास बनकर तैयार हुआ अचानक से सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ता मिलने लगी। अचानक सब कुछ पाकर एक सपने जैसा लग रहा है। सगे-संबंधियों के साथ-साथ समाज में उनकेमान-सम्मान में उत्तरोरत वृद्धि भी हुई है। अब जीवन खुशियों से भर गया है। टीम के अधिकारी श्री हर्षल एवं श्री राम राजू के साथ नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी दिनेश्वर यादव एवं सीएलटीसी के अपराजिता, श्रीनिवास आदि उपस्थित थे।

पीएम आवास के लाभुक श्री सुशांत सोरेन से बातचीत करते इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन सस्टेशन टीम के सदस्यगण।

पीएम आवास के कार्यों में गति लाने के लिए मुहिम हुई तेज

राज्यभर के नगर निकायों में एकरारनामा शिविर का आयोजन

सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से शहरी गरीबों एवं आवासविहीनों के अपने घर का सपना साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है। निदेशालय भी इन सभी जरूरतमंदों के पक्के आवास के सपने को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है एवं योजना के सफल और सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए हर छोटी-बड़ी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए योजना से सम्बन्धित कार्यों को मूर्त रूप दे रहा है। डीएमए की कोशिशों का ही नतीजा है कि राज्यभर में अब तक योजना अंतर्गत 86,772 गरीबों एवं आवासविहीनों के पास खुद का पक्का मकान है। खास बात यह है कि डीएमए लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने की मुहिम में पूर्व की भांति नए वित्तीय वर्ष में भी पूरे उत्साह एवं जोश खरोश के साथ कार्यशील है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) घटक-4 (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड में 25,443 आवास बनाने की स्वीकृति केंद्र ने दी है। अब राज्य में इन सभी लोगों का आवास योजना के माध्यम से बन सकेगा। राज्यभर के 46 नगर निकायों में स्वीकृत कुल 25,433 आवासों में सबसे अधिक आवास 3347, 2497 एवं 2345 क्रमशः गिरिडीह नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम एवं देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत किये गयें हैं।

डीएमए के निदेशक श्री राजेश कुमार पाठक के पहल पर निदेशालय के ही तत्वावधान में स्वीकृत आवासों के जल्द निर्माण, कार्यों में तीव्रता, लाभुकों के सहूलियत एवं कार्यों में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं का त्वरित निराकरण एवं लाभुकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से दिनांक 21.04.2022 से 23.04.2022 तक सभी नगर निकायों में एकरारनामा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से कम समय में सभी लाभुकों का एकरारनामा कार्य को पूरा किया जा सके एवं स्वीकृत आवासों के निर्माण के लक्ष्य को ससमय पूरा किया जा सके। इसके लिए नगर निकायों को कैंप लगाकर तीन दिनों में लाभुकों के साथ एकरारनामा कराने का लक्ष्य दिया गया था और इस लक्ष्य को सभी नगर निकायों ने शत-प्रतिशत हासिल भी किया। शिविर के माध्यम से लाभुकों का एकरारनामा करते हुए उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी वितरित किया गया।

नगर निकायों में एकरारनामा शिविर का आयोजन, चयनित 25,433 लाभुकों के आवास निर्माण के लिए किया गया एकरारनामा

पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत दीप प्रज्वलित कर एकरारनामा कार्यक्रम का शुभारंभ करते निकाय के पदाधिकारी।

शीर्ष 5 नगर निकायों के एकरारनामा कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्रम संख्या	निकाय का नाम	स्वीकृत आवासों की कुल संख्या	एकरारनामा पूर्ण
1.	गिरिडीह	3347	3167
2.	मेदिनीनगर	2497	2150
3.	देवघर	2345	2203
4.	रांची	1121	1052
5.	हजारीबाग	1096	1008

राज्य के सभी 46 नगर निकायों में एकरारनामा शिविर की कुल उपलब्धियां : **23,747**

रांची नगर निगम

शिविर में लाभुकों के जागरूकता पर दिया गया विशेष बल

शिविर के माध्यम से लाभुकों को योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। लाभुकों को आवास निर्माण से संबंधित पहलुओं के साथ-साथ विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाले अनुदान राशियों सम्बन्धी जानकारियाँ जैसे नींव खुदाई के साथ ही प्रथम किश्त की राशि का लाभुकों के खाते में हस्तांतरण, एवं लाभुकों को आवास पूर्ण करने की समय सीमा 8 माह यानी 240 दिन में करने के विभिन्न चरणों एवं प्रक्रियाओं से विस्तारपूर्वक अवगत कराते हुए जल्द आवास निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। लाभुकों को आवास निर्माण कार्य को तीव्र गति से मूर्त रूप देने का संकल्प भी दिलाया गया। आवास निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए सभी लाभुकों को कार्यालय के टॉल फ्री नं. 1800-120-2929 एवं विभिन्न जानकारियों सहित लीफलेट का भी वितरण किया गया। जिससे की लाभुकों को आवास निर्माण के समय किसी भी तरह की समस्या नहीं हो और कार्यो को तीव्र गति से पूरा किया जा सके।

पीएम स्वनिधि का मिला सहारा, मुश्किलों से हुआ किनारा

श्रीमती जानकी देवी अपने सब्जी दूकान के साथ।

श्रीमती जानकी देवी, पति श्री सुरेन्द्र साव, बड़की सरैया नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर-06 की निवासी हैं। ये कई वर्षों से फुटपाथ पर सब्जी बेचकर पूरे परिवार का भरण-पोषण करते आ रहीं हैं। इनका व्यवसाय अच्छा-खासा चल रहा था। मगर कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से इनकी दुकानदारी पूरी तरह से ठप हो गया। कई महीनों तक लगातार लॉकडाउन के कारण इनके द्वारा सालों से अर्जित जमा-पूंजी भी धीरे-धीरे पारिवारिक खर्चे में खत्म हो गई। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। आर्थिक स्थिति ख़राब होने के चलते परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब पूर्ण लॉकडाउन के बाद आंशिक रूप से लॉकडाउन हटा तो इनके सामने दुकान को नए सिरे खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान उनकी मुलाक़ात सीआरपी दीदी अनीता देवी से हुई और उनके द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारें में विस्तृत जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद उनका चेहरा ख़ुशी से चमक उठा था। इनके द्वारा तुरंत उक्त योजना के लाभ के लिए बड़की सरैया नगर पंचायत कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन किया गया। तत्पश्चात, इन्हें बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से उक्त योजना के तहत ₹10,000/- रुपये का ऋण मिला। योजना का लाभ मिलने से मानो अब इनके सपनों के पंख लग गए। मन में आत्मविश्वास का संचार होने लगा।

इससे उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा सब्जियों की बिक्री के लिए बाजार से बड़े पैमाने पर सब्जी खरीदने में मदद मिली। ₹10,000/- रुपये का पुनर्भुगतान करने के उपरांत अब ये ₹20,000/- रुपये ऋण लेने का मन बना रहीं हैं। अब वे हर माह ₹6,000 से ₹7,000/- रुपये आसानी से कमा ले रहीं हैं। इसके लिए श्रीमती जानकी देवी जी ने केंद्र व राज्य सरकर तथा बड़की सरैया नगर पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभार जताया है। साथ ही साथ वह पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए अपने पड़ोसियों व सगे-संबंधियों को प्रेरित भी कर रहीं हैं।

आर्या स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ पेश कर रहीं हैं सफलता की नज़ीर

सरकार झारखंड की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत रूप से सक्षम बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में डे-एनयूएलएम योजना के तहत फुसरो नगर परिषद द्वारा आर्या स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। इस समूह में कुल 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

व्यवसाय को रफ़्तार देकर बन रहीं हैं प्रेरणा का स्रोत: स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ सरकार से रिवॉल्विंग फंड 10,000/- रुपये एवं बैंक से 01,00,000/- रुपये का ऋण लेकर आजीविका को गति देने के लिए अचार, पापड़, बड़ी एवं चिप्स आदि बनाकर व्यवसाय को ज़ोर-शोर से रफ्तार दे रहीं हैं। इस व्यवसाय से जुड़ी सभी महिलाएं अपनी आजीविका के साथ-साथ बैंक ऋण का भुगतान भी ससमय कर रहीं हैं। जिससे ये महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।

अचार, पापड़, बड़ी चिप्स का व्यवसाय कर जीवन को दें रहीं रफ्तार

आर्या स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ

पंचसूत्र के पालन को लेकर महिलाएं हैं गंभीर

इनके द्वारा बेहतर प्रतिफल के लिए साप्ताहिक बैठक का आयोजन कर आजीविका संवर्द्धन हेतु कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जाता है। पंचसूत्र का पालन करने को लेकर महिलाएं गंभीर दिखाई पड़ती हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम भी समय-समय पर दिखाई पड़ते हैं। समूह से जुड़ी सभी महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यो में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पूर्व में स्वच्छता अभियान, कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता अभियान में समूह की भागीदारी अत्यंत प्रशंसनीय रही है। इन लोगों द्वारा सर्वप्रथम कोविड का वैक्सीन लिया, उसके उपरांत और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। जो सराहनीय कदम रहा है।

चेहरे पर खिल उठी मुस्कान पीएम आवास योजना से मिला पक्का मकान

ज्योति सिन्हा पति-अनिल सिन्हा देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 रांगा मोड़ निवासी है। इनके परिवार में 4 सदस्य है। पति-पत्नी एक बेटा और एक बेटी। ये गरीबी में भी बहुत खुशहाली से रहते थे। ज्योति सिन्हा घर से ही कपड़े की सिलाई कर एवं अनिल सिन्हा ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चला रहे थे। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। ये लोग दो कमरों में अपना जीवन गुजार रहे थे, जो कि कर्कट का बना हुआ था। जब बरसात का मौसम आता था तो इनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, टूटे कर्कट से पानी घर में भर जाता था। जिस कारण अपने निजी जिन्दगी में परेशानी बढ़ती ही थी साथ ही व्यवसाय पर भी असर पड़ता था। दूसरे के कपड़ों पर पानी और गंदा गिर जाता था जिसके कारण ज्योति के ग्राहक वर्षा ऋतु में कपड़े सिलने नहीं देने लगे। व्यवसाय धीमी होने से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी।बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता था। गर्मी के दिनों में अत्याधिक गर्मी और वर्षा में पानी और गंदगी झेलकर जैसे-तैसे घर में रह रहे थे।

हमारा सपना... गरीब का हो घर अपना

ज्योति के लिए अपना एक पक्का मकान होना बहुत जरूरी था, जिससे वे अपनी जीविका सही से चला सके लेकिन दोनों पति-पत्नी की आय इतनी नहीं होती थी कि ये अपने लिए एक पक्का मकान बना सके। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पक्के मकान के सपने को पूरा करना इनके लिए असंभव सा था। अंततः इन्हें विज्ञापनों एवं वार्डों में लगाए गए कैम्प से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में पता चला और इन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। आवेदन देने के कुछ ही दिनों के अंदर ही इनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ। अब तो मानों इनके वर्षों पुराने सपने को पंख लग गया। योजना के तहत सरकार द्वारा उन्हें कुल सहयोग राशि 2,25,000/- विभिन्न किस्तों में निर्धारित समयावधि पर प्राप्त होते गयी। कुछ ही समय में देखते ही देखते इन्होंने सहयोग राशि से अपने सुन्दर सपने के आशियाने का निर्माण पूर्ण कर ली। सरकार के सहयोग से इनके इस नए घर में सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस घर में इनका पूरा परिवार अब काफी सुख-शांति व सुकून के साथ रह रहा है।

अब इनके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। श्रीमती ज्योति सिन्हा का सिलाई का काम घर पक्का होने से बहुत आगे बढ़ गया, इनके ग्राहकों को इनपर विश्वास होने लगा और काम बढ़ने से आमदनी भी अच्छी होने लगी है। इनके पति घर में भी अब बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाने लगे जिससे भी इनकी आमदनी पहले की अपेक्षा बढ़ी।

इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक तरफ जहाँ ज्योति सिन्हा के परिवार को पक्का घर दिया वहीं दूसरी तरफ इनके सिलाई और ट्यूशन के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया।

अपने नए आवास में सिलाई का कार्य करती PMAY(U) लाभुक ज्योति सिन्हा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों एवं आवासविहीनों को न केवल घर मिल रहा है, बल्कि यह लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने, रोजगार देने, समाज में एक नया पहचान देने का भी कार्य कर रहा है। एक तरह से योजना के लाभ से सामाजिक आर्थिक एवं व्यक्तिगत जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है।

व्यवसाय को गति मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। बच्चों को भी पढ़ाई करने में अब कोई परेशानी नहीं होती है। सारा परिवार बहुत खुशी के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं। श्रीमती ज्योति सिन्हा ने बताया की ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' के आने से उनका और पूरे परिवार का सपना साकार हुआ और वे अब खुशी-खुशी जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय भी काफी आगे बढ़ा लिया है। आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई है। उनका परिवार बहुत खुश है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाये गए इस योजना के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं देवघर नगर निगम को बहुत-बहुत धन्वाद दिया।

ज्योति सिन्हा का पूर्व का कच्चा मकान।

योजना अंतर्गत निर्मित पक्का मकान।

डे-एनयूएलएम योजना के घटक सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास के तहत ALF का किया जा रहा गठन

नेतृत्व, उद्यमशीलता एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने का हो रहा प्रयास

धनवार नगर पंचायत

शहरी गरीब महिलाओं का उत्थान, जीवन स्तर में सुधार और उनका सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण सरकार की सभी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। DAY-NULM योजना से महिलाओं को जोड़कर उन्हें लाभान्वित कर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में की जा रही निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि राज्यभर के नगर निकायों में अब तक 653 एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जा चुका है। योजना के माध्यम से शहरी गरीब महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में पहली बार झारखंड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम के तहत एएलएफ का निबंधन

निबंधन प्रमाण–पत्र

(झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन स्वावलम्बी सहकारी समिति के निबंधन के संबंध में)

प्रमाणित किया जाता है कि झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) (संशोधित 2015) की धारा–5 के अधीन उपरैली धनवार महिला विकास स्वावलम्बी सहयोग समिति लिमिटेड के नाम से एक समिति का विधिवत निबंधन मेरे कार्यालय में किया गया है। इस समिति का निबंधित कार्यालय उपरैली धनवार, पो० धनवार, थाना– धनवार, प्रखण्ड– धनवार, जिला– गिरिडीह, राज्य– झारखण्ड में है और कार्यक्षेत्र धनवार नगर पंचायत, वार्ड सं०– 03 अर्थात शहरी क्षेत्र अंतर्गत है।

समिति की निबंधन संख्या– JKD 02 03 01 OTH 02 2022 है।

समिति की उप–विधियाँ भी निबंधित कर दी गयी है।

इस प्रमाण– पत्र पर मैंने आज दिनांक 21-04-22 को हस्ताक्षर किया है और मोहर लगायी है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी

नगरीय प्रशासन निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के देख-रेख में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत धनवार नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत गठित एरिया लेवल फेडरेशन का पंजीकरण झारखंड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (झारखंड अधिनियम 2, 1997) (संशोधित 2015) की धारा 5 के अधीन उपरैली ''धनवार महिला विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड'' के नाम से एक समिति का विधिवत निबंधन कराया गया है। समिति के अध्यक्ष पूनम देवी, सचिव नीलम देवी एवं कोषाध्यक्ष संजू देवी है। इसी प्रकार धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत भी योजना अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर संगठन (ALF) का पहली बार झारखंड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम के तहत ''शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड'' नाम से निबंधन कराया गया। इस स्वावलंबी सहकारी समिति की अध्यक्ष रूबी देवी, सचिव रंबा श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष सविता देवी हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास के तहत शहरी गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले उन्हे स्वयं सहायता समूह में जोड़कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध करायी जाती है। ऐसे ही छोटे-छोटे समूहों को जोड़कर राज्य में अब क्षेत्र स्तरीय संघ (Area Level Federation-ALF) का गठन भी तीव्र गति से किया जा रहा है। राज्य के सभी शहरी नगर निकायों के सभी वार्डों में एक-एक एएलएफ गठन करना सुनिश्चित किया गया है। कुल 1140 एएलएफ का गठन किया जाना है। क्षेत्र स्तरीय संघ की एक इकाई में 10-20 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। महिला समूहों को बड़े संगठनात्मक संरचना में एकजुट अर्थात एएलएफ के गठन से स्वयं सहायता समूह के सदस्य को ऋण प्रस्ताव तैयार करने, समूह की महिलाओं को बैंक से संपर्क करवाने एवं स्वयं सहायता समूह के सुगम संचालन यथा ऋण प्रस्ताव तैयार करने एवं खाता खुलवाने इत्यादि विभिन्न पहलुओं सहित वर्तमान सदस्यों के क्षमता निर्माण में व्यापक रूप से सहायक सिद्ध हो रही है। अब तक राज्यभर में सबसे अधिक 56 एएलएफ का गठन धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किया गया है। वहीं जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र अंतर्गत 52 एएलएफ का गठन किया है।

इन समितियों के पंजीकरण होने के पश्चात विभाग द्वारा समिति को ₹50,000/- का रिवाल्विंग फंड भी विमुक्त किया गया। समिति का उद्देश्य सदस्यों को आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक सामाजिक एवं परिवारिक स्तर पर संपूर्ण विकास में सहयोग करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारस्परिक सहायता की भावना जागृत करना है और इन के संपूर्ण विकास करने की व्यवस्था करना समिति का मूलभूत उद्देश्य होगा। समिति स्वयं उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी तथा आवश्यकता अनुसार उन संगठनों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे रचनात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है।

रामगढ़ नगर परिषद की नयी पहल, लाभुक रोजगार अभियान

(PMAY-U) लाभुकों का MSY योजना अंतर्गत किया जा रहा है निबंधन

सरकार राज्य के अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अति गंभीर एवं कृत संकल्पित है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। परिणाम और प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रयास का परिणाम दिखने भी लगा है, वर्तमान में योजना अंतर्गत राज्य भर के सभी (50) शहरी नगर निकायों में 57,647 जॉब कार्ड बनाने के साथ-साथ 11,01,482 मानव दिवस कार्य भी आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि लाभार्थी श्रमिकों को नरेगा जॉब कार्ड की तरह ही श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके तहत वह योजना से मिलने वाले रोजगार के लाभ को प्राप्त करते हैं।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) 14 अगस्त 2020 में शुरू की गयी थी। कोरोना संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटे रहे थे। रोजगार का अभाव झेल रहे इन दिहाड़ी मजदूरों की समस्या का निवारण करने के लिए योजना शुरू की गयी थी। अमृत योजना के तहत शहरों में हो रहे आधारभूत संरचना निर्माण, सड़क, नाली निर्माण, पौधारोपण, पार्क सौंदर्यीकरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्य, नदी तालाब सौंदर्यीकरण कार्य, भवन निर्माण कार्य एवं अन्य विभागों द्वारा विकास क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं में श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। परन्तु अब योजना के कार्य का दायरा विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य भर के विभिन्न नगर निकायों में भवन निर्माण कार्य में भी श्रमिकों को कार्य आवंटित किये जा रहे हैं।

आवास के साथ-साथ रोजगार के लिए राज्य भर के नगर निकायों में चलाये जा रहे इस तरह के अभियान से PMAY(U) लाभुकों एवं अकुशल श्रमिकों में ख़ुशी है। श्रमिकों ने इस तरह की पहल के लिए नगर निकायों के अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया है।

- बेरोजगारों/अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी
- राज्य के सभी 50 शहरी नगर निकायों में अकुशल श्रमिकों का MSY में निबंधन एवं रोजगार

योजना के तहत रामगढ़ नगर परिषद में चलाया जा रहा विशेष अभियान

डीएमए के तत्वावधान में रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विशेष पहल के तहत अभियान चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के वैसे लाभार्थियों को, जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निबंधित किया जा रहा है। ताकि, आवास के साथ-साथ उनके रोजगार की भी समस्या का समाधान किया जा सके। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में PMAY(U) के घटक-4 अंतर्गत 1189 लाभुकों का चयन आवास निर्माण के लिए किया गया है। क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर चलाये जा रहे इस लाभुक रोजगार अभियान के तहत नए वित्तीय वर्ष के सभी PMAY(U) लाभार्थियों का योजना अंतर्गत 25 अप्रैल 2022 तक श्रमिक कार्ड बनाने के लक्ष्य को बखूबी हासिल किया गया।

डे-एनयूएलएम योजना से जुड़ कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं शहरी गरीब

गरीबों के सपनों में लगी पंख, जीवन में भर रही खुशियों की रंग

डीएमए के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से राज्यभर में महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। नगर निकायों में शहरी गरीब महिलाओं को भिन्न-भिन्न बैंकों से लोन मुहैया कराकर उनके स्वरोजगार को गति देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

डीएमए द्वारा योजना के तहत शहरी गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम रंग ला रही है। कौशल्या देवी जो मानगो नगर निगम अंतर्गत संचालित कल्याणी महिला समिति नामक स्वयं सहायता समूह से जुडीं हैं और बैंक से क्रेडिट लिंकेज का लाभ प्राप्त कर सिलाई-कढ़ाई का कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहीं हैं। योजना से जुड़ने के पूर्व इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सिलाई एवं कढ़ाई का कार्य तो उन्हें आता था परन्तु उचित पूंजी के अभाव में वो अपने व्यवसाय को गति देने में असमर्थ थीं। कौशल्या देवी बताती हैं कि ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर कौशल्या देवी अपने व्यवसाय को गति देने के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर आगे बढ़ने का विचार किया। लेकिन उन्हें पता ही नही था कि किस योजना का लाभ मुझे कैसे मिल सकता है?

इसी क्रम में मानगो नगर निगम कार्यालय द्वारा इन्हें डे-एनयूएलएम योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कार्यालय कर्मियों को जैसे ही उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी हुई उन्होंने तत्काल योजना के SEP-I घटक के तहत इनका आवेदन फॉर्म भरवाया। आवेदन भरवाने के उपरांत टास्क फोर्स कमेटी के अनुमोदन के पश्चात आवेदन को बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड पुरुलिया रोड शाखा में लोन स्वीकृति हेतु भेजा गया। मानगो नगर निगम कार्यालय के सी.एम.एम.यू. कोषांग के द्वारा बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए कौशल्या देवी को बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो शाखा से ₹50,000/- का लोन दिलाया गया।

कौशल्या देवी लोन प्राप्त करने के उपरान्त लेडीज कॉर्नर खोली और अपने सिलाई-कढ़ाई के व्यवसाय को एक नयी रफ्तार दी। इनका कहना है कि शहरी गरीब लोगों को इस योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए तथा अपने व्यवसाय को आर्थिक मजबूती देना चाहिए। आज वो अपने इस कार्य से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहीं हैं। बच्चों का नामांकन भी क्षेत्र अंतर्गत एक निजी विद्यालय में करवाया है। कौशल्या देवी के स्वरोजागर के प्रति इच्छाशक्ति, लगन और आत्मनिर्भरता को देखकर उनके ससुराल के लोग भी उनकी तारीफ़ करने से नहीं थकते।

सिलाई का कार्य करती कौशल्या देवी।

पिछले वित्तीय वर्ष में मानगो नगर निगम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के आधार पर कई शहरी गरीबों को इस योजना का लाभ विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए दिलाया गया है। क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत सीएमएम, सीओ, एवं सीआरपी दीदी द्वारा कई बैंकों में दौरा कर लाभुकों को लोन दिलाने में सहयोग किया जा रहा है एवं इस वित्तीय वर्ष में भी बैंकों के सहयोग से अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु कार्ययोजना बनाकर तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है।

युवाओं को हुनरमंद एवं रोजगारपरक ट्रेनिंग देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

प्रशिक्षणोंपरांत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ग्रहण करतीं नाज़िया नवास।

हर हाथ को काम राज्य को मिल रही नई पहचान

नर्स का कार्य करतीं नाज़िया नवास।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वे लोग अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है नाज़िया नवास की। नाज़िया नवास हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरदार रोड कुरैशी मुहल्ला की रहने वाली हैं। ये बहुत ही साधारण परिवार से सम्बन्ध रखतीं हैं। नाज़िया का एक छोटा भाई एवं एक छोटी बहन है। इनके पिताजी का राशन की एक छोटी सी दूकान है। जिसके सीमित आय से परिवार का भरण-पोषण होता था। बहुत मुश्किल से जीवन-यापन हो रहा था। नाज़िया अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी है इसलिए इसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। वो स्थानीय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से अपनी डिग्री की पढाई पुरी की। अब उसके सामने बेरोजगारी और घर की परिस्थितियाँ सामने मुँह बाए खड़ी थी।

इसी बीच नाज़िया को 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के EST&P घटक अंतर्गत संचालित 'आर्यभट्ट एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट' की जानकारी मिली। जो युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। नाज़िया ने विधिवत यहाँ अपना नामांकन करवा लिया और हेल्थ केयर क्षेत्र अंतर्गत General Duty Assistant (GDA) कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ GDA के साथ-साथ जॉब Oriented प्रशिक्षण पाकर नाज़िया को काफी हद तक आगे बढ़ने में मदद मिली। नाज़िया बतातीं हैं की यहाँ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ कम्यूनिकेशन स्किल एवं कम्प्यूटर की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें निगम की स्वच्छता अभियान से भी जुड़ने का मौका मिला। इस अभियान के तहत इन्होने अपने साथ के कुछ प्रशिक्षणार्थियों के साथ निगम क्षेत्र के अलग-अलग गली मुहल्ले में जा कर स्वच्छता अभियान के कार्यो को आगे बढ़ाने का कार्य किया।

नाज़िया यहाँ से प्रशिक्षण पाकर अपने ही गृह जिले हजारीबाग के 'आरोग्य हॉस्पिटल' में नर्स का काम करतीं हैं। यहाँ उन्हें ₹12,000/- प्रति माह वेतन मिलता है। अपने वेतन से अब वो अपनी जरूरतों को पूरा करती है और परिवार की मदद भी करती है। पारिवारिक आर्थिक स्थिति में भी पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। जिससे अब उसका और उसके परिवार की स्थिति में भी बदलाव आया है। नाज़िया का आत्मनिर्भर होना लोगों के लिए प्रेरणा बन रहीं हैं और उसके प्रति समाज के नजरिए में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

राज्य भर के विभिन्न नगर निकायों के युवा योजना के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर ना केवल आजीविका पा रहें हैं बल्कि वे आज आत्मनिर्भर होने के साथ निरंतर सफलता के नए आयाम गढ़ रहें हैं।

कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पृथ्वी दिवस पर आयोजित किया गया पेंटिंग प्रतियोगिता

पृथ्वी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र स्थित समिति के सभागार में 'पेन्ट योर बैग' पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें स्कूली बच्चों के साथ जेएनसी के ब्रांड एंबेस्डर भी शामिल हुए और पर्यावरण एवं पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया गया।

चित्रकारी करते जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार।

पेंटिंग प्रतियोगिता में कार्यालय के अधिकारी एवं बच्चों ने अपनी प्रतिभा को जुट बैग के ऊपर रंगों से उभारा। एक तरफ जहाँ स्वच्छता एवं जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई वहीं जुट बैग पर बच्चों ने पर्यावरण संबंधी चित्र बनाए और समाज को प्रेरक सन्देश दिए। पेंटिंग के माध्यम से बच्चों नें धरती को बचाने और संवारने के लिए संदेश देने के साथ-साथ अपनी प्रतिभा को भी पेंटिंग के द्वारा जुट बैग पर उकेरा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के साथ भी जोडना है। ताकि, वे भविष्य में प्रकृति को बेहतर बनाए रखने में अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाएं। साथ ही कला के माध्यम से बहुत बड़ा सामाजिक संदेश दिया जा सकता है। यही संदेश यहां बच्चों ने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से दिया है।

बच्चों द्वारा इस ''पेंट योर बैग'' प्रतियोगिता में भाग लेकर पर्यावरण विषय पर बनायीं गयी पेंटिंग काफी सराहनीय भी हैं। ''पेंट योर बैग'' प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स का कैनवास माध्यम से जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

जुट बैग पर बच्चों द्वारा बनाया गया पेंटिंग।

औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की गाथा

जमशेदपुर कार्यालय की तस्वीर

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) का गठन तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1924 में किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्यकारी शक्तियां टिस्को या अन्य कंपनियों के अधिकारियों के पास सुरक्षित थी। शहरी विकास अनुभाग द्वारा वर्ष 1998 में जेएनएसी को भंग कर दिया गया एवं डीसी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को समिति के संचालन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। तदोपरांत, वर्ष 2006 में शहरी विकास खंड, रांची, झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। स्मरणीय हो कि वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) के संस्थापक पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौशरवान जी टाटा के नाम से इस शहर की बुनियाद पड़ी। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता व खड़कई एवं सुवर्णरेखा नदी से आसानी से पानी की सुलभता के कारण ही आज यहाँ के आधुनिक शहर का बीजारोपण किया गया। इस शहर को वर्ष 2019 में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का सम्मान भी मिला है।

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समितिः एक नज़र में

कुल क्षेत्रफल
56.32 वर्ग किलोमीटर

औसत साक्षरता दर
86.91 %

कुल जनसंख्या
6,77,350

पुरूष : 353,212
महिला : 324,138

विशेष पदाधिकारी : श्री कृष्ण कुमार

प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल

डिमना झील	रसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस
जुबली पार्क	भाटिया पार्क
टाटा स्टील	भुनेश्वरी मंदिर
जूलॉजिकल पार्क	नदी मिलन
हुडको झील	

भाषा : हिंदी, खोरठा, बंगला, संथाली

योजना एक नजर में

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-PMAY(U)

जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र अंतर्गत PMAY(U) के घटक-3 (किफायती आवास परियोजना) के तहत बिरसानगर एवं बागुनहातु में कुल लक्ष्य क्रमशः 9592 एवं 2480 के विरूद्ध 7372 एवं 500 आवास के निर्माण पर कार्य किया गया है। बिरसानगर आवासीय परियोजना में लॉटरी के माध्यम से 3836 आवास दिव्यांग, वरीष्ठ एवं सामान्य नागरिकों को आवंटित किया जा चूका है। नवजीवन कुष्ठ आश्रम, देवनगर, बाराद्वारी, साकची में लक्ष्य 400 के विरूद्ध 352 आवास पूर्ण कर लाभुकों को उपलब्ध कराया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

डे-एनयूएलएम योजना के तहत कुल 522 स्वयं सहायता समूह का गठन कर ₹ 10,000/- की दर से चक्रिय निधि उपलब्ध कराया गया है। कुल 44 एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है एवं निबंधन का कार्य किया जा रहा है। 233 शहरी गरीब तथा 118 स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार योजना से जोडकर रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (EST&P) घटक के तहत 1170 प्रतिभागियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही Assessment एवं Certification करते हुए Placement भी दिया जा रहा है। क्षेत्र अंतर्गत कुल चार आश्रयगृहों जैसे बारीडीह एवं बर्मामाइन्स में पारिवारिक आश्रयगृह, साकची में महिला आश्रयगृह तथा सीतारामडेरा बस स्टैण्ड अवस्थित पुरूष आश्रयगृह का संचालन एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। RPL (Recognition of Prior Learning) के तहत कुल 265 पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर Assessment एवं Certification किया जा रहा है।

पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2571 पथ विक्रेताओं को ₹ 10,000/- की प्रथम किश्ता तथा 196 पथ विक्रेताओं को द्वितीय किस्त की राशि ₹ 20,000/- उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY)

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कुल 5834 श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाकर 32 योजनाओं में 1579 श्रमिको को 100 दिन का कार्य प्रदान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)

स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को झारखण्ड के सभी निकायों में प्रथम एवं सम्पूर्ण भारत में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को देशभर में दूसरा एवं झारखण्ड के सभी निकायों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसके तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को पांच करोड की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सम्पूर्ण झारखण्ड में एकमात्र निकाय है जिसे Garbage Free City के अन्तर्गत स्टार रेटींग में 3 Star Rating अवार्ड प्राप्त है।

प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग योजना (PMFME)

प्रधानमंत्री फूड प्रोसंसिंग योजना के तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 33 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोडा गया है एवं उनको योजना के लाभों से जोडकर लाभान्वित किया जा रहा है।

डीएमए के तत्वावधान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारियों ने लक्ष्य के अनुसार उक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए निकाय क्षेत्र के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। डीएमए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

संरक्षक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

संपादक
श्री विनय कु. चौबे
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यकारी संपादक
श्री राजेश कु. पाठक
निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग

यह बुलेटिन विभाग के कार्यों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है।

दैनिक अखबारों में
प्रकाशित खबरों की संक्षिप्त झलकियाँ...!

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Follow us on : @JharkhandDMA , Website : dmajharkhand.in

1st Floor, JUPMI Building, Beside H.E.C Headquarter, Dhurwa, Ranchi -834004, Jharkhand